□□□□□□□□□□□□□ □□□□

जनसत्ता 31 मई, 2014 : लोकसभा चुनाव में तीस बरस बाद किसी □क पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, अच्छी बात है□ केंद्र में पहली बार अपने बूते □क गैर-कांग्रेसी दल ने सरकार बनाने का दम दिखाया है, और भी अच्छी बात है□ यहां हम 1977 के चुनाव की विजेता जनता पार्टी को नहीं गिन रहे, क्योंकि वह □क दल नहीं, अनेक पार्टियों के विलय से बना गठबंधन था□ लेकिन ताजा चुनाव के जश्न में डूबी जनता को निम्न तथ्यों पर भी गौर करना चाहि□□ आज से पहले स्पष्ट बहुमत पाने वाली पार्टी को कभी भी चालीस फीसद से कम वोट नहीं प□□ इस बार महज इकत्तीस प्रतिशत वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी ने दो सौ बयासी सीटें जीत ली हैं□

सोलहवीं लोकसभा में दागी और करो□पति सांसदों की संख्या में खासी वृद्धि हुई है□ देश की सबसे ब□ी पंचायत में स्थान पाने वाले जनप्रतिनिधियों में बयासी प्रतिशत करो□पति और चौंतीस फीसद दागी हैं□ ये आंक□े चौंकाते हैं□ बताते हैं कि हमारी संसद का चेहरा कैसा है□ अब से दस बरस पहले लोकसभा में तीस फीसद सांसद करो□पति और चौबीस प्रतिशत आपराधिक मामलों के आरोपी थे□ मतलब यह कि दस साल में करो□पति सांसदों की संख्या में बावन प्रतिशत और दागियों की जमात में दस फीसद का इजाफा हो गया है□ संकेत खतरनाक है□

मोदी सरकार के तीस फीसद मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं और इक्यानबे प्रतिशत करो□पति हैं□ सार्वजनिक जीवन में शुचिता की समर्थक बिरादरी को ये आंक□े निराश करते हैं□ □सोसि□शन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (□डीआर) ने नई सरकार के छियालीस में से चौवालीस मंत्रियों के हलफनामे का जायजा लेने के बाद उक्त जानकारी सार्वजनिक की□ प्रकाश जावडेकर और निर्मला सीतारमण संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, इस कारण उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है□

□डीआर के अनुसार, चौवालीस में से आठ मंत्रियों (अठारह प्रतिशत) के विरुद्ध हत्या के प्रयास, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, अपहरण और चुनाव नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप हैं□ मोदी की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की औसत संपत्ति 13.47 करो□ रुप□ है□ सबसे ज्यादा दौलत वित्तमंत्री अरुण जेटली (□क सौ तेरह करो□ रुप□) के पास है, जबकि सबसे कम, जनजाति मामलों के मंत्री मनसुख भाई धनजीभाई वसावा (पैंसठ लाख रुप□) के पास□

संसद को देश की जनता का प्रतिबिंब माना जाता है□ जब राष्ट्र की लगभग □क चौथाई आबादी कंगाल (गरीबी रेखा के नीचे) हो और तीन चौथाई से ज्यादा लोग दो जून की रोटी के लि□ खटते हों, तब सांसदों की औसत संपत्ति करो□ों में होने को क्या माना जा□? यह बात दावे से कही जा सकती है कि भारत की □क तिहाई जनता के खिलाफ पुलिस थानों में मामले दर्ज नहीं हैं□ फिर क्या कारण है कि इस बार चुनाव जीतने वाले □क तिहाई से ज्यादा सांसद दागी हैं? विजयी सांसदों में से अनेक के खिलाफ तो हत्या, डकैती, अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं□

आम चुनाव में धनबल और बाहुबल के ब□ते प्रभाव को मापने के लि□ कुछ और बातें बताना जरूरी है□ इस बार चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या में अप्रत्याशित पचास फीसद की वृद्धि हुई□ 2009 में जहां 5435 उम्मीदवार ख□े हु□, वहीं 2014 में उनकी संख्या ब□कर 8163 हो गई; इनमें से 2208 (सत्ताईस फीसद) करो□पति थे, जबकि जीतने वाले करो□पतियों की संख्या बयासी प्रतिशत है□ इसी प्रकार कुल 1398 (सत्रह प्रतिशत) दागियों ने चुनावी दंगल में भाग्य आजमाया, लेकिन विजयी दागियों का आंक□ा चौंतीस फीसद रहा□ इसका अर्थ यही हुआ कि धनबल और बाहुबल से चुनाव

जीतने की संभावना भी ब□ जाती है□

□डीआर के अनुसार, चुनाव में साफ-सुथरी छवि के प्रत्याशियों के मुकाबले दागियों की विजय की संभावना दुगुनी होती है□ इसी प्रकार धनपतियों की अपेक्षा मामूली हैसियत वाले उम्मीदवार के हारने का आंक□ा काफी ऊंचा है□

टिक□ट बांटते समय अब हर पार्टी अपने प्रत्याशी की जीत की संभावना को प्राथमिकता देती है□ जीत के ला□ जाति और धर्म के साथ-साथ धनबल और बाहुबल भी तोला जाता है, इसलि□ ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता अक्सर पार्टी टिक□ट पाने की दौ□ में पिछ□ जाते हैं□ साफ-सुथरी राजनीति का दावा करने वाली देश की दोनों ब□ी पार्टियां भी दागियों और धनपतियों के मोह में बुरी तरह जक□ी हैं□ हालिया चुनाव जीतने वाले भाजपा के □कतिहाई से ज्यादा सांसद दागी हैं और उनमें से बीस फीसद के खिलाफ गंभीर आरोप हैं□ कांग्रेस के अठारह प्रतिशत विजयी प्रत्याशी दागी हैं और उनमें से सात फीसद के खिलाफ थानों में गंभीर अपराध से जु□ मामले दर्ज हैं□ क्षेत्रीय दलों की स्थिति तो और भी बुरी है□

राजग के शत-प्रतिशत सांसद दागी हैं, जबकि शिवसेना के अठारह में से पंद्रह और राकांपा के पांच में से चार सांसद दागी हैं□ आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद चुनने में उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र अव्वल हैं□ लेकिन धनी जनप्रतिनिधि चुनने में इस बार आंध्र प्रदेश ने सबको पीछे छो□ दिया है□ वहां तेलुगू देशम, टीआर□स और वाइ□सआर कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय दलों से चुने ग□ सांसदों की औसत संपत्ति पचास करो□ रुप□ से अधिक है□ संसद के निचले सदन में आ□ कांग्रेस के चौवालीस सांसदों की औसत संपत्ति सोलह करो□ रुप□ और भाजपा के टिक□ट पर जीते दो सौ बयासी सांसदों की ग्यारह करो□ रुप□ है□

सबसे कम संपत्ति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (औसत उन्यासी लाख रुप□) के सांसदों की है□ यहां □क और दिलचस्प तथ्य बताना जरूरी है□ अध्ययन से पता चलता है कि दुबारा चुनाव ल□ने वाले सांसदों की संपत्ति में पांच साल के भीतर 289 प्रतिशत ब□ोतरी हुई है जो ब□े-ब□े कॉरपोरेट घरानों को चौकाती है□ आज किसी धंधे में इतना मुनाफा नहीं दिखता□ हम यहां हलफनामे में घोषित संपत्ति का जिक्र कर रहे हैं□ यह बात खुला भेद है कि हमारे ज्यादातर जनप्रतिनिधि जितनी संपत्ति घोषित करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अघोषित दौलत उनके पास है□

इस चुनाव की □क और विसंगति का जिक्र जरूरी है□ परिणाम बताते हैं कि महज इक्तीस फीसद वोट के साथ भाजपा ने स्पष्ट बहुमत पा लिया है, जबकि 19.3 प्रतिशत वोट पाने के बावजूद कांग्रेस को केवल चौवालीस सीटें मिली हैं□ इन आंक□ों की गहराई में जा□ तो पता चलता है कि भाजपा ने □कतिहाई से कम जन-समर्थन के बावजूद लोकसभा की लगभग बावन फीसद सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि कुल वोटों का पांचवां हिस्सा पाने के बावजूद कांग्रेस को मात्र आठ फीसद सीटें मिलीं□ मौजूदा चुनाव व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वह विजयी घोषित कर दिया जाता है□ कई बार जब मैदान में अनेक उम्मीदवार होते हैं तब मात्र बीस फीसद मत पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है□

इस दोषपूर्ण व्यवस्था को समझने के ली□ कुछ और उदाहरण देना जरूरी है□ ताजा चुनाव में मायावती की पार्टी बसपा ने उत्तर प्रदेश में अच्छे-खासे बीस प्रतिशत वोट पा□, लेकिन उसका □क भी सांसद नहीं चुना गया□ दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सा□ सात प्रतिशत वोट पाकर भी दो सीटें और अपना दल ने महज □क प्रतिशत वोट के साथ दो सीटें जीत लीं□ भाजपा और कांग्रेस के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बसपा 4.1 प्रतिशत वोट के साथ तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन मौजूदा लोकसभा में उसका □क भी सांसद नहीं है□

ऐसी वचित्रि स्थति अन्य राज्यों में भी दोहराई गई है। तमलिनाडु में द्रमुक 23.6 फीसद वोट पाने के बावजूद □ कभी सीट नहीं पा सकी। इसी प्रकार पश्चमि बंगाल में वाम मोर्चे ने तीस प्रतशित जन-समर्थन पाया, लेकनि उसके दो ही सांसद जीते। कांग्रेस ने मात्र 9.6 प्रतशित वोट पा□, लेकनि उसके चार उम्मीदवार जीत ग□, जबकि भाजपा 16.8 प्रतशित वोट पाने के साथ दो सीटें जीती।

बहिार में लालू यादव की पार्टी राजद 20.1 प्रतशित वोट पाने के बावजूद मात्र चार सीट जीत पाई, जबकि रामवलिास पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी को महज 6.4 प्रतशित वोट मलि और उसके छह प्रत्याशी जीते। नीतीश कुमार की पार्टी जद (□) 15.8 फीसद वोट पाने के बावजूद केवल दो प्रत्याशी जताने में कामयाब रही। दल्लिी की कहानी भी कम दलिचस्प नहीं है। यहां अरवदि केजरीवाल की पार्टी को वोट तो तैंतीस प्रतशित मलि, लेकनि सीट □ कभी नहीं मलि पाई। 44.6 प्रतशित वोट के साथ भाजपा ने सौ फीसद (सातों) सीटें जीत लीं।

उक्त तथ्यों से पता चलता है कि हमारे लोकतंत्र की बुनयिाद कतिनी कमजोर हो गई है। आज चुनावी राजनीति पर धनबल और बाहुबल हावी है। आम चुनाव में खर्च की अधकितम सीमा सत्तर लाख रुप□ है, जबकि ब□ दलों के उम्मीदवार इससे पंद्रह से बीस गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। कहने को संवधिान प्रत्येक नागरकि को चुनाव ल□ने का अधकिार देता है, लेकनि हकीकत में आम आदमी इस अधकिार को आजमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता।

मौजूदा व्यवस्था में उसका काम वोट डालना भर रह गया है। चुनाव ल□ने का साहस कुछ दल और उनके असरदार नेता ही कर सकते हैं। अनुमान है कि इस चुनाव पर लगभग पचास हजार करो□ रुप□ फूंके ग□, जसिका अधकितर हस्सिा औद्योगकि घरानों से मलि□ बनिा कॉरपोरेट जगत के सहयोग के कसिी पार्टी का चलना या चुनाव ल□ना अब लगभग असंभव हो गया है।

हमने चुनाव की जो प्रणाली अपनाई है वह सत्तारू□ पार्टी या ब□ दलों को ही भाती है। हमारी व्यवस्था में जो प्रत्याशी सर्वाधकि मत पाता है वह जीत जाता है। वास्तव में यह प्रणाली ही समस्त चुनावी बीमारियों की ज□ है। इसके कारण धनबल और बाहुबल को ब□ावा मलिा है और अनेक बार अच्छे-खासे वोट पाने वाली पार्टयिों का □ कभी उम्मीदवार संसद में नहीं पहुंच पाता है।

आज यूरोप के अधकितर देशों में आनुपातकि चुनाव (प्रोपोरशनल रप्रिजेंटेशन) व्यवस्था लागू है। इस प्रणाली में जसि पार्टी को चुनाव में जतिने प्रतशित वोट मलिते है, उसके उतने ही प्रतनिधि संसद में होते हैं। इसमें मतदान कसिी प्रत्याशी के लि□ नहीं, पार्टी के पक्ष में होता है। उदाहरण के लि□, चुनाव में अगर भाजपा को इक्तीस, कांग्रेस को उन्नीस, बसपा को चार और वाम मोर्चे को चार प्रतशित वोट प□ तो इसी अनुपात में उनके सांसद चुने जा□ंगे।

इस व्यवस्था को अपनाने से गलाकाट चुनावी स्पर्धा से मुक्ति मलि जाती है और धनबल और बाहुबल से जीतने वाले प्रत्याशयिों पर अंकुश लग जाता है। साथ ही संसद में देश और समाज के हर तबके को उसकी संख्या के आधार पर प्रतनिधित्वि मलि जाता है। धर्म और जाति की राजनीति करने वाले दल भी अंतत: नरिर्थक हो जाते हैं। आशा है सरकार और समस्त दल इस प्रणाली को अपनाने पर वचिार करेंगे।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- https://www.facebook.com/Jansatta

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिए क्लिक करें- https://twitter.com/Jansatta